SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

भारतीय उच्च्व शिक्षा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के योगदान पर अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षा शास्त्रविभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

सार

आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य एक नया भारतीय बाजार मॉडल बनाना है जो मुख्य रूप से देश के जिलों और छोटे शहरों में सूक्ष्म अर्थव्यवस्थाओं के विकास के माध्यम से कायम है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक संपत्ति अब आबादी के शीर्ष 5% तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के हर आम नागरिक के सशक्तिकरण के लिए खरीदी जाएगी। आत्मनिर्भरता मॉडल कॉरपोरेट्स के साथ सहयोग करके और मिश्रित अर्थव्यवस्था को संतुलन देकर जनता का विश्वास हासिल करने पर केंद्रित है। प्राथमिक उद्देश्य नैतिक अभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है जो दुनिया को त्रस्त कर रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों के बीच धन और संसाधनों का समान वितरण कर रहा है।

मुख्य शब्द - संसाधन, अर्थव्यवस्था, कार्याबल, नवाचार, पूंजी निवेश, कारपोरेट, संगठन

प्रस्तावना

भारत को कुशल बनाने के लिए एक अच्छी और शिक्षाप्रद तकनीक का उपयोग नहीं किया गया तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए ये सभी अस्थायी उपाय विफल हो जाएंगे। स्थानीय शिक्षा (स्थानीय के लिए मुखर) के माध्यम से स्थानीय चिंताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया परियोजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कई अन्य सहित कई नीतियों की घोषणा की है। इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के पहले के पश्चिमी मॉडल का भारतीयकरण करना है और बाजार मुख्य रूप से पश्चिम के सिद्धांतों द्वारा शासित है ताकि मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड में बदल दिया जा सके और **हिंदू दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार** मानवता की बेहतर सेवा की जा सके जिसे "वसुधैव कुटुम्बकम" कहा जाता है। ।"

भारत को अपनी आर्थिक प्रणाली के माध्यम से इस तरह बदलने की कोशिश करना और बदलना निश्चित रूप से एक कठिन काम है, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यापक परिवर्तन हो। केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना ही काफी नहीं होगा क्योंकि भारत की औपनिवेशिक, पश्चिमी-प्रभावित आर्थिक व्यवस्था ने केवल पूंजीपतियों को पैदा किया। संपूर्णता में स्पष्ट परिवर्तन वास्तव में अधिक समय की आवश्यकता है। वैश्विक

अर्थव्यवस्थाएँ चल रहे COVID-19 मुद्दे के परिणामस्वरूप अनुबंध कर रही हैं। हालांकि, कई लोग इसे नए उत्पादों और समाधानों को पेश करने के अवसर के रूप में देखते हैं। COVID-19 के बाद के वातावरण में संगठन बहुत अलग तरीके से काम करेंगे, और नवाचार के लिए बहुत जगह है। भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें विश्व की सबसे पुरानी सजीव सभ्यता है। इसके अलावा, उन्होंने भारत द्वारा अपनाए गए निजीकरण और पूंजीवाद के पिछले आर्थिक मॉडल की कमियों और भारत के कार्यबल के विकास पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। ब्रेन ड्रेन और विशेषज्ञ कामगारों की एक बड़ी संख्या का आना-जाना, जो नौकरी के लिए विदेश गए या अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम किया, भारत के विकास में बहुत कम योगदान दे रहे थे।

COVID-19 अंतर-मंत्रालयी सूचनाएं

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि हम कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। भारत के नागरिकों के सक्रिय समर्थन से, हम अब तक वायरस के प्रसार को कम करने में सक्षम रहे हैं। वायरस से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है नागरिकों को सटीक जानकारी के साथ सशक्त बनाना और उन्हें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी की जा रही सलाह के अनुसार सावधानी बरतने में सक्षम बनाना। COVID -19 अंतर-मंत्रालयी अधिसूचना वेबसाइट विभिन्न मंत्रालयों से COVID-19 संबंधित सूचनाएं एक ऐसे प्रारूप में प्रदान करके कुशलतापूर्वक इस उद्देश्य को पूरा करती है जो सुलभ है, S3WaaS ढांचे का उपयोग करके बनाया गया है , जो सुरक्षित और स्केलेबल है। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत द्वारा निभाई गई अनुकरणीय भूमिका को व्यापक रूप से पहचाना और सराहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन को वर्ष 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है । यह कार्यकारिणी बोर्ड के 147 वें सत्र के दौरान एक वर्चुअल आयोजित बैठक में हुआ। उन्होंने जापान के डॉ हिरोकी नकटानी से पदभार ग्रहण किया।

माननीय पीएम द्वारा इस कठिन समय का उपयोग आत्मानिर्भर (आत्मनिर्भर) बनने के आह्वान को भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को सक्षम करने के लिए बहुत अच्छी तरह से किया गया है। प्रचुर मात्रा में सावधानी बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए अनलॉक 1 दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिससे प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी जा सके।

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं

अर्थव्यवस्था

आधारभूत संरचना

प्रणाली

जीवंत जनसांख्यिकी और

मांग

आत्मनिर्भर भारत के पांच चरण हैं:

चरण-I : एमएसएमई सहित व्यवसाय

चरण-II : गरीब, जिसमें प्रवासी और किसान शामिल हैं

चरण-III : कृषि

चरण-IV : विकास के नए क्षितिज

चरण-V : सरकारी सुधार और समर्थकारी

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ

अर्थव्यवस्था - एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो इंक्रीमेंटल बदलाव के बजाय क्वांटम जंप लाए।

Infrastructure - एक ऐसा Infrastructure जो आधुनिक भारत की पहचान बने।

सिस्टम - एक ऐसा सिस्टम जो तकनीक से संचालित हो जो 21वीं सदी के सपनों को साकार कर सके; एक प्रणाली जो पिछली शताब्दी की नीति पर आधारित नहीं है।

Demography - दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी Vibrant Demography ही हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है।

डिमांड - हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, वह ताकत है, जिसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने की जरूरत है।

केंद्रीय वित्त मंत्री की शिक्षा के क्षेत्र में तत्काल पहल की घोषणा

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की जाएगी जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। यह शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करेगा, और इसमें शामिल हैं: दीक्षा (एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) जो अब सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा बन जाएगा; टीवी (एक कक्षा-एक चैनल) जहां कक्षा 1 से 12 में से प्रत्येक के लिए प्रति ग्रेड एक समर्पित चैनल गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा: स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए MOOCS प्रारूप में SWAYAM ऑनलाइन पाठ्यक्रम; IITJEE/NEET की तैयारी के लिए IITPAL; सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई शिक्षा वाणी पॉडकास्ट के माध्यम से प्रसारित; और डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डेज़ी) पर और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित अलग-अलग विकलांगों के लिए अध्ययन सामग्री। इससे देश भर के लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ होगा।

वैश्विक महामारी के इस समय में, यह महत्वपूर्ण है कि हम छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करें। मनोदर्पण पहल एक वेबसाइट, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, सलाहकारों की राष्ट्रीय निर्देशिका, इंटरएक्टिव चैट प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से इस तरह की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही है। इस पहल से देश में स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता, शिक्षकों और शिक्षकों को भी लाभ होगा। स्कूली शिक्षा में हितधारकों का समुदाय।

सरकार मुक्त, दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा नियामक ढांचे को उदार बनाकर उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग का विस्तार कर रही है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी शुरू करेंगी ऑनलाइन कोर्स साथ ही, पारंपरिक विश्वविद्यालयों और ओडीएल कार्यक्रमों में ऑनलाइन घटक को भी वर्तमान 20% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। यह विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 7 करोड़ छात्रों को सीखने के बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने वाले छात्रों के लिए अनुभवात्मक और आनंदपूर्ण सीखने के साथ-साथ महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक और संचार कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम भारतीय लोकाचार में निहित होना चाहिए और वैश्विक कौशल आवश्यकताओं के साथ एकीकृत होना चाहिए। इसलिए, वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार छात्रों और भविष्य के शिक्षकों को तैयार करने के लिए स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक बचपन के चरण के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा 202 तक ग्रेड 3 में आवश्यक रूप से मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान प्राप्त कर ले, एक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन शुरू किया जाएगा। , सीखने के परिणाम और उनके मापन सूचकांक, मूल्यांकन तकनीक, सीखने की प्रगति का पता लगाने आदि को एक तरह से आगे ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

व्यवस्थित फैशन। यह मिशन 3 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 4 करोड़ बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करेगा।

घोषित किए गए समग्र वित्तीय पैकेज में आरबीआई द्वारा घोषित उपायों से उत्पन्न तरलता भी शामिल है।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) घटाया गया जिसके परिणामस्वरूप 1,37,000 करोड़ रुपये की तरलता सहायता मिली।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत उधार लेने की बैंकों की सीमा बढ़ा दी गई। इसने बैंकों को कम MSF दर पर अतिरिक्त 1,37,000 करोड़ रुपये की तरलता का लाभ उठाने की अनुमति दी।

एनबीएफसी और एमएफआई सहित निवेश ग्रेड बांड, वाणिज्यिक पत्र, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के कुल 1,50,050 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।

म्यूचुअल फंडों को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता सुविधा (SLF) की घोषणा की गई।

नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के लिए नीति रेपो दर पर 50,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं की घोषणा की गई।

सभी प्रकार के ऋणों के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर किश्तों के भुगतान और ब्याज पर तीन महीने की मोहलत प्रदान की गई है।

2019 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। और डॉ के कस्तूरीरंगन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 29 जुलाई 2020 को, केंद्र सरकार ने स्कूलों और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में 'परिवर्तनकारी सुधार' के लिए एनईपी-2020 को मंजूरी दे दी है और सतत विकास लक्ष्यों-2030 के अनुसार शिक्षा में पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के वादे किए हैं। एनईपी आत्म

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

निर्भर भारत के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में भारत को बदलने और एक समग्र शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इसे आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना करता है। एनईपी सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के बीच उनके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सोच, कौशल विकास, समस्या को सुलझाने और बहु-विषयक दृष्टिकोण के लोकाचार को रेखांकित करता है।

सार्वभौमीकरण - प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से माध्यमिक तक आधारभूत संरचना समर्थन, अभिनव शिक्षा केंद्र, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से।

छात्र केवल रटने की तुलना में अधिक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

छात्र अध्ययन के लिए विषयों के चुनाव में अधिक लचीलापन होगा।

पाठ्यचर्या की सामग्री को कम करना और आवश्यक सीखने और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना छात्र कम उम्र में भी वैज्ञानिक सोच का पोषण करते हैं। समृद्ध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ, जब तक छात्र अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेते, तब तक वे वैश्विक मानकों के अनुरूप हो जाएंगे। हमारे देश में स्थापित किए जा रहे विदेशी कॉलेजों के साथ अधिक वैश्विक प्रदर्शन भारत अधिक विदेशी छात्रों को शिक्षा के लिए आकर्षित करेगा।

व्यावहारिक कार्य और कौशल विकास को अतिरिक्त महत्व दिया जाता है, छात्रों के लिए संगीत, कला और साहित्य का एक्सपोजर छात्रों को कक्षा 6 से पढ़ाए जा रहे व्यावसायिक कौशल और कोडिंग के बारे में अधिक जानने का मौका मिलता है।

खोज, चर्चा और विश्लेषण के साथ-साथ महत्वपूर्ण सोच के साथ सीखने की एक नई लहर का रास्ता एक विशिष्ट और क्रिया-उन्मुख नीति जो परिणाम-संचालित है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर जोर देता है। अनुसंधान और निजी संस्थानों को वित्त पोषण पर जोर संयुक्त और सहयोगी अनुसंधान, प्रकाशन और विद्वानों का मार्गदर्शन अनुसंधान का क्षेत्रीयकरण और शोध एवं प्रकाशन में मातृभाषा का प्रचार-प्रसार।

बेहतर गुणवत्ता और सीखने के परिणामों की उपलब्धि

एनईपी 2020अपनी नीति में भारतीय शिक्षा को एक वैश्विक मानक बनाने और विद्यार्थियों के बीच दक्षता पैदा करने के उद्देश्य से एक नीति जनादेश के रूप में इंटरैक्टिव और व्यावहारिक कक्षा पर जोर देती है, जिससे वे अपनी खुद की आजीविका के लिए सक्षम हो सकें। यह नीति कला, विज्ञान, प्रबंधन और

मानविकी पर एक साझा फोकस के साथ एक नौकरी उन्मुख ट्रांस-डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम की कल्पना करती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि एक आत्मनिर्भर (आत्मानिर्भर भारत) की दिशा में लक्ष्य को साकार किया जा सके। वास्तव में, एनईपी वास्तव में एक सावधानीपूर्वक, पद्धतिगत, भविष्यवादी और टिकाऊ नीति है यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो निश्चित रूप से आत्म निर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

निष्कर्ष

आत्मानबीर भारत अभियान विभिन्न सरकारी सुधारों और राहत उपायों के साथ समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत करने की दिशा में एक मिशन है। महामारी के दौरान भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी का मुकाबला करने के अलावा, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी जी का यह मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था को हर संभव पहलू में आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है।

सन्दर्भ

- "पीएम मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए 5-I फॉर्मूला पेश किया, कहते हैं 'हम निश्चित रूप से अपनी वृद्धि वापस प्राप्त करेंगे'" । जागरण अंग्रेजी । 2 जून 2020। 10 नवंबर 2021 को लिया गया ।
- "12.5.2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का अंग्रेजी प्रतिपादन" । pib.gov.in (प्रेस सूचना ब्यूरो) । प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार। 12 मई 2020. मूल से 23 मई 2020 को पुरालेखित । 10 नवंबर 2021 को पुनःप्राप्त ।
- मोहंती, प्रसन्ना (14 नवंबर 2020)। "रीबूटिंग इकोनॉमी 45: आत्मनिर्भर भारत क्या है और यह भारत को कहां ले जाएगा?" . बिजनेस टुडे । मूल से 14 नवंबर 2020 को पुरालेखित । 14 मार्च 2021 को पुनःप्राप्त ।
- " आत्मानबीर भारत आत्म-संयम नहीं : पीएम ने वैश्विक निवेशकों को आश्वासन दिया" । आउटलुक इंडिया । 9 जुलाई 2020 । 12 सितंबर 2020 को पुनःप्राप्त ।
- जोशी एट अल। 2021, पृ. 1.
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होस्ट किया गया । (27 मई 1998)। "प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी: पोखरण (हिंदी) में परमाणु परीक्षणों पर वक्तव्य" । डिजिटल लाइब्रेरी, लोकसभा, भारत की संसद । 14 दिसंबर 2021 को मूल से संग्रहीत - डिजिटलीकरण इकाई, लोकसभा सचिवालय के माध्यम से ।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (27 मई 1998) द्वारा होस्ट किया गया। "प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी: पोखरण में परमाणु परीक्षण पर वक्तव्य"। डिजिटल लाइब्रेरी, लोकसभा, भारत की संसद। 13 दिसंबर 2021 को मूल से संग्रहीत - डिजिटलीकरण इकाई, लोकसभा सचिवालय के माध्यम से।
- "ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020"। भाषाएँ .oup.com। 12 मई 2020. मूल से 13 मार्च 2021 को पुरालेखित। 13 मार्च 2021 को पुनःप्राप्त। वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द है… आत्मानिर्भरता या आत्मनिर्भरता।
- गोपालकृष्णन, गीता (2002), एमएस स्वामीनाथन। वन मैन्स क्वेस्ट फॉर ए हंगर-फ्री वर्ल्ड (पीडीएफ), शिक्षा विकास केंद्र, इंक, पीपी। 122, 128, मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत 17 मार्च 2007युवा रोजगार शिखर सम्मेलन 2002 के लिए उत्पादित
- त्रिवेदी, मधुर (5 जून 2020)। "आत्मनिर्भरता एक प्रक्रिया है प्रधानमंत्री जी, जो आपसे बहुत पहले शुरू हुई थी"। नेशनल हेराल्ड। 28 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त।
- सरुक्कई 2021 , पृ. 357.
- सरुक्कई 2021, पी। 364.
- श्रीवास्तव, असीम (1 अक्टूबर 2019)। "150 पर गांधी: वह प्राकृतिक स्व-शासन में विश्वास करते थे"। डाउन टू अर्थ। 6 अक्टूबर 2019 को मूल से संग्रहीत। 22 अक्टूबर 2021 को पुनःप्राप्त। ...गांधी और रवींद्रनाथ दोनों स्पष्ट हैं कि इस तरह के स्व-शासन को राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष के लिए कम नहीं किया जा सकता है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जैसे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का गठन किया।
- सरकार, शांखनील, सं. (19 फरवरी 2021)। "नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी: पीएम मोदी"। हिंदुस्तान टाइम्स। मूल से 19 फरवरी 2021 को पुरालेखित। 11 नवंबर 2021 को पुनःप्राप्त।
- "मेक इन इंडिया, आत्मानबीर भारत महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की नई परिभाषाएँ: अमित शाह"। आउटलुक इंडिया। 30 जनवरी 2022। 8 फरवरी 2022 को पुनःप्राप्त।
- पीटीआई (30 जनवरी 2022)। "मेक इन इंडिया, आत्मानबीर भारत महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की नई परिभाषाएँ: अमित शाह"। उदयवाणी। 8 फरवरी 2022 को पुनःप्राप्त।
- "स्वदेशी"। अहिंसा के लिए मेटा केंद्र। 3 मई 2009। मूल से 12 अक्टूबर 2014 को पुरालेखित। 1 अक्टूबर 2020 को पुनःप्राप्त।